

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—236/2019/225 (2019/00236)

1. तुलछारामू पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी हाथीखेड़ा चौराहा, फॉय—सागर, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व० सींगा, जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध आदेश विद्वान लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 7.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1/2016.

उपस्थित:—

1. श्री चन्द्रपकाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैराकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 2.

## निर्णय

दिनांक:— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 7.6.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोंडेंट ने अधी०न्याया० उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत पेश कर प्रतिवादी/अपीलांट को वाद के निर्णय तक निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी०न्याया० ने आदेश दिनांक 7.6.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० 1955 स्वीकार कर अपीलांट को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया । अधी०न्याया० के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया । रेस्पोंडेंट के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने वादपत्र व प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296, 1297, 1299, 1313/2465 की समस्त भूमियों में 1/5 हिस्से का तथा अपीलांट/प्रतिवादी 4/5 हिस्से का सहिस्सेदार खातेदार के रूप में दर्ज

है । अधी०न्याया० ने अधी०न्याया० के समक्ष जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादी/रेस्पो० के कथनों का खण्डन किया कि वादग्रस्त भूमि मौके पर बाहमी विभाजन से वादी अपने 1/5 तथा अपीलांट 4/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा पक्षकारान सहखातेदार हैं जिनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है इसके उपरांत भी अधी०न्याया० ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर, अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण को निर्णित कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई किये गलत रूप से पक्षकारान व उनके वकीलों की उपस्थिति दर्ज करते हुए जिस प्रकार से पारित किया गया है वह विधिक के बाध्यकारी प्रावधानों एवं न्याय, नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ही नहीं किया जबकि प्रकरण रेस्पो० संख्या 2 राज०सरकार के जवाब में विचाराधीन था । अधी०न्याया० ने मात्र सरसरी तौर पर संक्षिप्त आदेश पारित किया है जिसमें प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का भी विवेचन नहीं किया गया है जिससे भी अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में पारित किया गया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अधिवक्ता से संपर्क करने पर दिनांक 25.6.2019 को हुई जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी राजस्व वाद में नियमित रूप से हाजिर होते आ रहे हैं । आदेश दिनांक 7.6.2016 की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही । अपील जानकारी होने के बावजूद 3 वर्ष के विलंब से पेश की गई है जो क्षम्य योग्य नहीं होकर अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है ।
7. प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष रेस्पो०/वादी द्वारा अपीलाधीन भूमि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296, 1297, 1299, 1313/2465 भूमि ग्राम हाथीखेड़ा तहसील अजमेर में वादी/रेस्पो० का 1/5 हिस्सा एवं अपीलांट का 4/5 हिस्सा है तथा विवादित भूमि का आज तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है परन्तु अपीलांट/प्रतिवादी बिना बंटवारे के ही मौके पर रोड़ से लगती हुई भूमि पर कब्जा कर खेल मैदान बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा है तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है इस कारण अधी०न्याया० के समक्ष वादी/रेस्पो० द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा करवाये जाने के संबंध में वाद पेश किया गया तथा दौराने वाद विवादित संयुक्त सहिस्सेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध निर्माण न करने बाबत् एवं वादी/रेस्पो० को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल न करने बाबत् एवं भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश

किया गया था । अधी०न्याया० के समक्ष अपीलांत/प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु समय लेते रहे परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया । अधी०न्याया० द्वारा राजस्व कैम्प में दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवादित भूमि के संदर्भ में प्रार्थी के 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी का 4/5 हिस्सा की भूमि पर उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया है जिसमें अधी०न्याया० द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है । वाद बंटवारे के संबंध में है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर सहिस्सेदारी एवं कब्जा होता है । कोई भी पक्षकार बिना विधिक बंटवारे के निश्चित भूभाग पर न तो निर्माण कर सकता एवं न ही खुर्दबुर्द कर सकता है । अधी०न्याया० द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है एवं यह भी कथन किया कि अपीलांत उक्त आदेश से किस प्रकार व्यथित है इस संबंध में अपील मीमों में कोई कथन नहीं किया है । अतः अपील अपीलांत निरस्त की जावे ।

8. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम हम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांत ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । हम न्यायाहित में अपीलांत को सुना जाना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी०न्याया० की पत्रावली उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील अजमेर स्थित खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296 रकबा 0.06 है०, 1297 रकबा 0.010 है०, 1299 रकबा 0.03 है०, 1313 रकबा 0.04 है० एवं 1313/2465 रकबा 0.04 है०, समस्त भूमियां चाही प्रथम में वादी/रेस्पो० रामसिंह का 1/5 हिस्सा एवं अपीलांत/प्रतिवादी का 4/5 हिस्सा दर्ज होकर पक्षकारान की संयुक्त सहिस्सेदार की होकर अविभाजित आराजियात है जो संयुक्त कब्जे काश्त में है । स्वयं अपीलांत ने भी अपने अपीलमीमों में पैरा संख्या 2 में विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी एवं सहिस्सेदारी होने का कथन किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त सहिस्सेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि पर कोई भी पक्षकार बिना विधिक बंटवारे के विशिष्ट भू-भाग पर न तो निर्माण कर सकता है एवं न ही खुर्दबुर्द ही कर सकता है । अपीलाधीन भूमि का बंटवारा होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अधी०न्याया० की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांत/प्रतिवादी द्वारा वादी/रेस्पो० के प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० का जवाब ही पेश नहीं किया गया है तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में कैम्प हाथीखेड़ा में प्रकरण को रखकर एवं उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन भूमि बाबत् उभयपक्षों को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है जिसमें अधी०न्याया० द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पो०/वादी के पक्ष में पाया जाता है । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि पर बिना विधिक बंटवारे के किसी पक्षकार द्वारा निर्माण कराया जाता है अथवा खुर्दबुर्द की जाती है तो वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है । इस कारण अपूर्ण्य क्षति व असुविधा रेस्पो०/वादी को होने की संभावना है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांत खारिज

योग्य तथा अधीन्याया का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीन्याया द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बीएलमेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बीएलमेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर